

बेहतर समाज निर्माण में शिक्षकों की अहम भूमिका - कलेक्टर अवनीश शरण

उच्च शिक्षा अध्ययन संस्थान
में महोत्सव के द्वितीय सोपान
का भव्य आयोजन

बिलासपुर (विश्व परिवार)। आज उच्च शिक्षा अध्ययन संस्थान में वार्षिकोत्सव सत्र 2024-25 का भव्य उद्घाटन समारोह संपन्न हुआ। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में कलेक्टर अवनीश शरण एवं विशिष्ट अतिथि संयुक्त संचालक शिक्षा संभाग रामायण अदित्य अवनीश रहे।

कार्यक्रम की शुरुआत मशाल प्रन्जलन, धावक परिक्रमा एवं मशाल स्थापना के साथ हुई, जिसे बीएड प्रशिक्षार्थी रुक्मणी पैकरा एवं चंद्रशेखर सिंह ने संपन्न किया। इसके पश्चात महाविद्यालय की



नेतृत्व में भव्य मार्च पास्ट प्रस्तुत किया, जिसके विविध संस्कृतिक कार्यक्रमों ने सभा बंधा। अकारण का केंद्र बस्तरिया नृत्य दादर के कहवा तथा बिहु नृत्य रहा, जिसमें संस्थान के प्रशिक्षार्थियों ने मास्टर आफ सेरेमी करीम खान के

प्रस्तुति से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। महाविद्यालय की गतिविधियों एवं उपलब्धियों का प्रतिवेदन प्राचार्य ग्रे. मीता मुखर्जी द्वारा प्रस्तुत किया गया, जबकि प्रशिक्षार्थी प्रतिनिधि ऋषभ निवाद एवं छात्रावास प्रतिनिधि युवनाश

यादव ने समस्या एवं आवश्यकता से संबंधित मांगपत्र का वाचन किया एवं मांग पत्र सौंपा। विशिष्ट अति श्री रामायण अदित्य अपने उद्घोषन में विद्यार्थियों को शिक्षा एवं नैतिक मूल्यों की महता एवं छात्रावास प्रतिनिधि युवनाश

साझा किया। तथा इस अवसर पर कलेक्टर श्री शरण ने प्रशिक्षार्थियों के मांगपत्र पर शीघ्र कार्यवाही करने का आशासन दिया एवं प्रशिक्षार्थियों द्वारा किये गये शानदार मार्च-पास्ट एवं बैंड वाद की खूब तारीफ की। कलेक्टर ने प्रशिक्षार्थियों को अपने उद्घोषन से प्रेरित करते हुए अनुशासनबद्ध तरीके से आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। उन्होंने कहा कि बेहार समाज निर्माण में शिक्षकों की अहम भूमिका होती है क्योंकि वे अपने बाती गोपनीयों को तैयार करते हैं। उद्घोषन के पश्चात कलेक्टर महोदय ने उद्घाटन की विधिवत घोषणा की एवं ध्वजोतोलन के पश्चात रंग-बिरंगे गुब्बारे उड़ाकर समारोह का शुभारंभ किया। अतिथियों के समक्ष खेलकूद प्रतियोगियों में दर्ज 11 प्रकरणों में 101.394 युवाओं ने अपने बाती गोपनीयों को जिसके बाद सहायक प्राध्यायक डॉ. बी. व्ही. रमण राव द्वारा आभार प्रदर्शन किया गया। कार्यक्रम का सफल संचालन सहायक प्राध्यायक डॉ. संजय मनोहर आयदे ने किया संपूर्ण आयोजन उत्साह, उर्जा एवं शैक्षणिक उत्कृष्टता का प्रतीक रहा, जिसमें महाविद्यालय के आचार्य वृद्ध, महाविद्यालयीन स्टूडेंट्स एवं प्रशिक्षार्थियों ने सजिक सहायिता निभाई। आज के द्वितीय सोपान में गोला एवं तवा फेंक की प्रथम स्थान प्राप्त किया एवं सत्यम

की जानदेवी द्वितीय तथा सुन्दरम

मुंगेली (विश्व परिवार)। दिनांक 30.01.2025 को अवैध मादक पदार्थ जश्शुदा गांजा का नष्टीकरण किया गया है। मुंगेली में पुलिस कसान भोजराम पटेल द्वारा कार्यभार सम्बन्धने के पश्चात लगातार अवैध मादक पदार्थ विक्री एवं परिवहन करने वालों के विरुद्ध लगातार कार्यवाही की जा रही है, इसी अनुकूल में जिले में कुछ माह से की गयी 11 कार्यवाहीयों में दर्ज 11 प्रकरणों में 101.394 युवाओं ने अपने बाती गोपनीयों को जिसके बाद सहायक प्राध्यायक डॉ. बी. व्ही. रमण राव द्वारा आभार प्रदर्शन किया गया।

जिसके बाद द्वितीय सोपान का पौधा



संपादकीय

हिंडनबर्ग रिसर्च भंग

अमेरिकी निवेश व अनुसंधान कंपनी हिंडनबर्ग रिसर्च ने अचानक अपना कारोबार समेटने का ऐलान कर दिया। कंपनी के संस्थापक नेट एंडरसन ने अपने परिचितों, परिवार व मित्रों का हवाला देते हुए बेबसाइट पर पर्सनल नोट में लिखा- मैंने हिंडनबर्ग रिसर्च को भंग करने का फैसला किया है। नेट ने कहा यह अचानक लिया गया फैसला नहीं है। काफी सोच-समझकर लिया गया फैसला है। 2017 में हिंडनबर्ग रिसर्च का गठन करने वाले एंडरसन ने इसे अपने जीवन का एक अध्याय बताते हुए, जीवन का मुख्य केंद्र नहीं है कहा। अमेरिकी अकाउंटेंट हैरी माकरेपोलस को अपना रोल मॉडल मानने वाले एंडरसन ने ऐसे वक्त यह धोषणा की है, जब अमेरिका के नये राष्ट्रपति के तौर पर डोनाल्ड ट्रंप शपथ लेने वाले हैं। आलोचकों के अनुसार जॉर्ज सोरेस के साथ हिंडनबर्ग के कथित संबंधों व ट्रंप प्रशासन के दबाव का अंदेशा व्यक्त किया है। इस शॉर्ट सेलिंग कंपनी को 2024 में भारतीय बाजार नियामक संस्था सेबी द्वारा कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया था। क्योंकि कंपनी ने सेबी प्रमुख माध्यमी बुच पर वित्तीय धोखाधड़ी के आरोप मढ़े थे। उससे पहले हिंडनबर्ग ने देश के प्रमुख औद्योगिक समूह अडाणी पर गंभीर आरोपों द्वारा भारत में सुरिख्यां बटोरी थीं। समूह के मालिक गौतम अडानी पर अपनी ही कंपनियों के शेयरों में हेराफेरी कर सौ अरब डॉलर कमाने का आरोप था। रिपोर्ट सार्वजनिक होते ही अडानी ग्रुप को डेढ़ सौ अरब डॉलर का नुकसान होते ही वह विश्व के बीस अतिसमृद्धों की सूची से बाहर हो गए। हिंडनबर्ग की रिपोर्टेरों का हवाला देकर विपक्ष ने एकजुट होकर मोदी सरकार पर हमला बोल दिया था। हिंडनबर्ग ने अमेरिका के अलावा विदेशों की विभिन्न कंपनियों में गैर-कानूनी लेन-देन व वित्तीय अनियमितताओं का खुलास किया, जिससे उनके शेयर्स बुरी तरह ध्वस्त होने से उड़ें जबरदस्त नुकसान झेलना पड़ा। अरबपतियों व कुलीन वर्ग के साम्राज्य को हिलाने की जरूरत पर जोर देने वाली कंपनी के इस फैसले से खुश होने वाले भले ही चुनिंदा हैं मगर हतप्रभ रहने वाले लाखों हैं। असल में यह फैसला उसे क्यों लेना पड़ा, जब तक यह स्पष्ट नहीं हो जाता, हर कोई अपने-अपने क्यास लगाता रहेगा। दुनिया भर को अपने निशाने पर रखने वाले एंडरसन ने अभी अपनी भविष्य की योजनाओं के भी स्पष्ट संकेत नहीं दिए हैं। हो न हो, वह बड़ी तैयारी से कुछ अनोखा ही कर दिखाएंगे।

आलेख

राजनीति की गहरी परतों से रुबरू कराता पाताल लोक

ਪੰਕਜ ਦੁਖੇ

‘पाताल लोक’ के दूसरे सीज़न ने मनोरंजन के स्तर को नई ऊँचाई पर पहुंचा दिया है। जहां पहला सीज़न अपने उत्कृष्ट लेखन और दिलचस्प किरदारों के लिए मशहूर हुआ था, वहीं दूसरा सीज़न उस विरासत को और भी भव्यता के साथ आगे बढ़ाता है। इस बार की कहानी इंस्पेक्टर हाथीराम चौधरी (जयदीप अहलावत) और एसीपी अंसारी (इश्वाक सिंह) के ईर्द-गिर्द धूमती है, जो अपनी अपनी जांच के दौरान ऐसे मोड़ पर पहुंचते हैं, जहां उनकी राहें आपस में टकरा जाती हैं। 2025 की शुरुआत, दर्शकों के लिए वेब सीरीज़ की दुनिया में एक सुनहरा दौर लेकर आई है। पहले विक्रमादित्य मोटवानी की ‘ब्लैक वारंट’ ने दर्शकों का मन मोहा, और अब बहुप्रतीक्षित सीरीज़ ‘पाताल लोक’ के दूसरे सीज़न ने मनोरंजन के स्तर को नई ऊँचाई पर पहुंचा दिया है। जहां पहला सीज़न अपने उत्कृष्ट लेखन और दिलचस्प किरदारों के लिए मशहूर हुआ था, वहीं दूसरा सीज़न उस विरासत को और भी भव्यता के साथ आगे बढ़ाता है। इस बार की कहानी इंस्पेक्टर हाथीराम चौधरी (जयदीप अहलावत) और एसीपी अंसारी (इश्वाक सिंह) के ईर्द-गिर्द धूमती है, जो अपनी अपनी जांच के दौरान ऐसे मोड़ पर पहुंचते हैं, जहां उनकी राहें आपस में टकरा जाती हैं। इस टकराव के बाद उन्हें नागालैंड की ओर रुख करना पड़ता है, जहां एक बड़ी राजनीतिक और सामाजिक समस्या उभरती हुई दिखाई देती है। कहानी नागालैंड और दलिली के बीच धूमती है, जिसके केंद्र में नौर्झ ईस्ट के एक बड़े लीडर की देश की राजधानी में हुई राजनीतिक हत्या है, जिससे इस कहानी की शुरुआत होती है। सीरीज़ में तीन मुख्य पहलुओं को गहराई से उजागर किया गया है। पहला है मानवीय संवंधों की जटिलता। इस कहानी में घूमन रिलेशन्स और उनकी विविधताएँ दर्शाई जाती हैं। दूसरा है इस कहानी की विरासती विषयीता। इस कहानी में विविध विवरणों की विविधता दर्शाई जाती है, जिनमें से कुछ विविधताएँ दर्शाई जाती हैं। तीसरा है इस कहानी की विविधता दर्शाई जाती है, जिनमें से कुछ विविधताएँ दर्शाई जाती हैं।

बारोकाया पर बहुत गहराइ स काम किया गया ह। इस कहाना का लखनौ और इसकी मेकिंग इसे बस एक फ़िल्मी शो बनाने से बचाती है और ज़मीन से जोड़कर ही नहीं, बल्कि गाड़कर रखती है। फिर चाहे नागार्लैंड का केस हो और वहाँ मिले लोग या फिर जिंदगी की उथल पुथल में कई बार चक्की में पिसते अनजान और मासूम लोग, सभी किरदारों पर काफी एम्प्थी से नज़र डाली गई है। दूसरा अहम् पक्ष है, 'दोस्ती का महत्व और ताकत'। इस कहानी में किरदारों की दोस्ती और उस दोस्ती की ताकत को काफी वास्तविक तरीके से खेांकित किया गया है। कहानी के सभी सबप्लॉट्स इतने ज़मीनी और आम ज़िंदगी से जुड़े हुए लगते हैं, जैसे कि तमाम घटनाक्रम अपने आस पास के ही हों। पाताल लोक की कहानी का तीसरा मज़बूत आयम है इसके मुख्य किरदार इंस्पेक्टर हाथीराम चौधरी का अपने कर्तव्यों को निभाने का जुनून। वो हमेशा अपनी दाल रोटी चलाने वाली नौकरी और समाज व इंसानियत के प्रति अपनी डियूटी को अलग अलग परिभाषित करके जीता है। उसके लिए उसकी प्रतिबद्धता सिर्फ़ ऑफिस तक सीमित नहीं रह कर उसके दिल, उसकी भावना से जुड़े होते हैं और वो बिना अपनी परवाह किये बिना उसे सुलझाने में लगा रहता है। 'पाताल लोक' के क्रिएटर हैं सुदीप शर्मा जो इस ज़बरदस्त कहानी के लेखक भी हैं। सुदीप शर्मा के बारे में ये बता देना ज़रूरी है कि उन्होंने इससे पहले नेटफिल्क्स के लिए 'कोहरा' नाम की एक सीरीज़ बनाई थी जो कि पंजाब की पृथग्भूमि पर थी और काफ़ी सराही गई थी। बहरहाल, 'पाताल लोक' के औसतन 45 मिनटों वाले आठ एपिसोड्स के निर्देशक हैं अविनाश अरुण द्वारे। इस सीरीज़ में मुख्य कलाकार हैं जयदीप अहलावत, इश्वाक सिंह, गुलपनाग, तिलोत्तमा शोम, मरेनला इम्सोंग, एलसी सेकहोसे, नागेश कुकुनूर और कई अन्य छोटे बड़े लेकिन सब के सब दिग्गज कलाकार। जयदीप अहलावत ने फिर से यह साबित किया है कि वे इस समय के सबसे बेहतरीन अभिनेताओं में से एक हैं। उनके किरदार, इंस्पेक्टर हाथीराम चौधरी, की संवेदनशीलता और कड़वी सच्चाई को उन्होंने इतनी सजीवता से निभाया है कि दर्शक उनके हर कदम पर साथ चलने को मजबूर हो जाते हैं। उनकी डायरॉग डिलीवरी, हाव-भाव और भावनात्मक गहराई ने शो को और भी यादगार बना दिया है। उनके आलावा तिलोत्तमा शोम और सह कलाकारों की प्रभावशाली उपस्थिति है। तिलोत्तमा शोम, जो पुलिस अधीक्षक मेघना बरुआ के किरदार में है, ने अपने प्रदर्शन से शो को एक अलग स्तर पर पहुंचा दिया है।

उमेश चतुर्वेदी

धरेलू खर्च के इस नए आंकड़े को देखते वक्त हमें इस संदर्भ पर भी ध्यान देना होगा। बहरहाल हमें यह भी ध्यान देना होगा कि ग्रामीण इलाकों में खाद्यान्न विशेषकर गेहूं और चावल पर खर्च में निजी या पारिवारिक खर्च में कमी आई है। दुनिया की पांचवीं बड़ी अर्थव्यवस्था वाले अपने देश की पहचान उसके गांव रहे हैं। देश सिर्फ ग्रामीण संस्कृति और कृषि व्यवस्था के लिए ही नहीं, सहकार और शिल्पकारी के लिए भी वैश्विक पहचान रखते रहे हैं। सोने की चिड़िया कटे जाने वाले दौर में १५ शप्तमीया कृषि और अर्थिती

कह जान पाने दार न मा नारायण पृथि व आर जायका के आधार गांव ही रहे । यह बात और है कि अंग्रेजी शासन के दौरान से भारतीय गांवों का पतन शुरू हुआ । इसके बाद भारतीय गांव गरिबी और मजबूरी के पर्याय माने जाने लगे । लेकिन घरेलू उपयोग और खर्च के ताजा सर्वेक्षण की रिपोर्ट बता रही है कि गांवों की आर्थिक तस्वीर बदलने लगी है । भारत सरकार के सार्विकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की ओर से घरेलू उपयोग और खर्च के लिए कराए गए सर्वेक्षण के अनुसार शहरी और ग्रामीण इलाकों में घरेलू खर्च का जो पहले अंतर रहता था, वह लगातार घटता चला गया है । अगस्त 2023 से जुलाई 2024 के दौरान किए गए सर्वेक्षण के मुताबिक, ग्रामीण और शहरी भारत में प्रति व्यक्ति औसत मासिक खर्च 4,122 रुपये और 6,996 रुपये हो गया है । जबकि पहले यानी 2022 से 2023 के बीच यह खर्च क्रमशः 3,773 रुपये और 6,459 रुपये थाय् यानी शहरी और ग्रामीण भारत की प्रति व्यक्ति खर्च दर में बढ़ा अंतर था । मोटे तौर पर यह आंकड़ा बता रहा है कि हाल के दिनों में ग्रामीण इलाकों में आर्थिक समृद्धि पहले की तुलना में बढ़ी और उस तिहाज से खर्च भी बढ़ा है । 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की 68 प्रतिशत आबादी गांवों में रहती है, जबकि 32 प्रतिशत आबादी शहरों में है । स्वाधीन भारत में विशेषकर उदारीकरण के बाद जिस तरह का विकास मर्डल हमने अपनाया, उसमें शहरी विकास पर सबसे ज्यादा फेकेस रहा, ग्रामीण विकास या तो रस्मी रहा या फिर उस पर फेकेस शहरों की तुलना में कम रहा । शहरों की ओर रोजगार और जीवन सुविधाएं केंद्रित होती चली गई । शिक्षा के भी बेहतर अवसर गांवों की तुलना में शहरों की ओर बढ़ते गए । इस तिहाज से ग्रामीण क्षेत्रों से सबसे ज्यादा पलायन रोजगार और शिक्षा के लिए हुआ । फिर जिन

A photograph showing two farmers in a rice field. One farmer is in the foreground, bending over to harvest rice with a sickle. The other farmer is further back, also harvesting. A large pile of harvested rice lies on the ground between them. In the bottom right corner, the head of a dark-colored animal, possibly a cow or ox, is visible, wearing a harness. The background shows a rural setting with some buildings and trees.

परिवारों के पास सहूलियतें बढ़ीं, उन परिवारों ने अपनी हैसियत और बजट के लिहाज से मुफ्त पाए जाने वाले शहरों की ओर रहने के लिए रुख किया। यही वजह है कि शहरी और ग्रामीण आबादी का जो अनुपात आबादी के समय था, वह आज बदल चुका है। आजादी के बक्त तकरीबन 80 फीसद से ज्यादा लोग गांवों में रहते थे, अनुमान है कि वह घटें-घटते अब साठ और पैंसठ फीसद के बीच आ गई है। रिकॉर्ड पर ग्रामीण आबादी का इतना बड़ा हिस्सा भले ही गांवों में बसता हो, लेकिन हकीकत यह है कि इसमें एक बड़ा हिस्सा शहरों में रोजी-रोटी और शिक्षा के लिए कभी शौकिया तो कभी मजबूरीवश रहने को मजबूर है। इसलिए रिकॉर्ड की तुलना में वास्तविक ग्रामीण आबादी अब और भी कम हो चुकी है। घरेलू खर्च के इस नए आंकड़े को देखते बह इस संदर्भ पर भी ध्यान देना होगा। बहरहाल हमें यह भी ध्यान देना होगा कि ग्रामीण इलाकों में खाद्यान्न विशेषकर गेहूं और चावल पर खर्च में निजी या पारिवारिक खर्च में कमी आई है। इसकी वजह यह है कि सरकार की ओर से तमाम तरह की योजनाएं और सामाजिक कल्याण कार्यक्रम चल रहे हैं। मुफ्त खाद्यान्न योजना समेत कई अन्य सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों के जरिये मुफ्त में मिल रही चीजों की कीमतों को ध्यान में रखें तो घरेलू खर्च के ये आंकड़े ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए क्रमशः 4,247 रुपये और 7,078 रुपये हो जाते हैं। मौजूदा कीमतों के संदर्भ में देखें तो शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति खर्च पर औसत आठ और नौ प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। साल 2011-12 में शहरी

और खपत खर्च के बीच 84 प्रतिशत का अंतर था, जो 2022-23 में घटकर 71 प्रतिशत हो गया। जो अब 70 पैसेदार ही रह गया है। इन आंकड़ों से ग्रामीण इलाकों में बढ़ती खुशाली की तसवीर सामने आती है और अलावा की चीजों पर शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में यह खर्च 60 और 53 प्रतिशत रहा। इसका मतलब साफ है कि अब ग्रामीण इलाकों में भी वाहन, कपड़े, बिस्तर, जूते, मनोरंजन एवं टिकाऊ आदि सामानों पर खर्च बढ़ रहा है। इससे साफ है कि उपभोक्तावाद ने ग्रामीण इलाकों पर भी जोरदार दस्तक दी है। वैसे ऑनलाइन स्टोर से गांवों में खरीददारी बढ़ी है और उनके डिलीवरी एजेंटों की बाइकें अब ग्रामीण इलाकों का भी खुब चक्र लग रही हैं। पिछले साल मई में रिजर्व बैंक ने भी ग्रामीण इलाकों में बढ़ती खपत खर्च को लेकर ऐसे ही आंकड़े जारी किए थे। इन्हीं आंकड़ों के आधार पर रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने उम्मीद जताई थी कि भारतीय अर्थव्यवस्था में तेजी रहेगी और देश की जीडीपी दर में 7.3 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हो सकती है लेकिन रिजर्व बैंक ने इसी रिपोर्ट में ग्रामीण इलाकों में बढ़ते कर्ज को लेकर भी रिपोर्ट जारी की थी सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के रिपोर्ट में भी कर्ज को लेकर चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। इसके मुताबिक, कर्ज लेने में ग्रामीण क्षेत्रों के लोग कहीं ज्यादा आगे हैं। गांवों में प्रति एक लाख लोगों में 18,714 लोग ऐसे हैं, जिन्होंने कोई न कोइ कर्ज ले रखा है, जबकि शहरों में यह आंकड़ा 17,442 प्रति लाख ही है। साफ है कि उपभोक्तावाद ग्रामीण

संस्कृति को बदलने में बड़ी भूमिका निभा रहा है। कर्ज कभी गांवों के लोगों के लिए सिरदर्द होते थे, इसलिए वहां बचत केंद्रित अर्थकी पर जोर था। लेकिन अब इसमें गिरावट आई है। इसका मतलब साफ़ है कि गांवों में खर्च भले ही बढ़ रहा है, लेकिन यह भी सच है कि गांवों की तसवीर अभी कम से कम वैसी नहीं हो पाई है, जिस स्तर पर शहरी तसवीर है। गांवों का समृद्ध होना जरूरी है। हाल के दिनों में जनसंख्या को बढ़ाने और न बढ़ाने को लेकर सियासी तौर पर अपने-अपने तर्क दिए जा रहे हैं। इन तर्कों के अपने आधार हो सकते हैं। लेकिन इससे शायद ही कोई इनकार करेगा कि भारत के शहरों की सांस अगर पूल रही है तो इसकी बड़ी वजह उनकी ओर बेतहाशा हो रहा पलायन और उस बड़ी जनसंख्या के लिए इस्तेमाल हो रहे उपभोक्ता वस्तुओं का बड़ा योगदान है। भारत में आबादी बढ़ाने की जगह आबादी के समन्वित और संतुलित वितरण की जरूरत ज्यादा है। ग्रामीण इलाकों में आबादी को रोकने की कोशिश होनी चाहिए। ग्रामीण आबादी को बुनियादी शिक्षा और रोजगार गांवों या उसके आसपास ही उपलब्ध कराने की नीतियों पर आगे बढ़ाना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो निश्चित तौर पर आबादी को संतुलित किया जा सकेगा। तब गांव आबादी विहीन नहीं होंगे और शहरों पर आबादी का असंतुलित बोझ नहीं बढ़ेगा। गांवों में हो रही खपत और खर्च को लेकर आ रहे आंकड़ों का पहला असर यही होना चाहिए कि गांवों में आबादी रुके। लेकिन ऐसा होता नजर नहीं आ रहा है। ग्रामीण इलाके में बढ़ते खर्च से अबल तो गांवों में रोजगार के साधन बढ़ने चाहिए। लेकिन इस दिशा में ठोस बदलाव होते नजर नहीं आ रहे। बेशक आज आजादी के बाद के दौर की तरह के बदहात गांव नहीं हैं। बेशक शहरों जितना उसे बिजली नहीं मिलती, लेकिन पहले की तुलना में अब गांवों को भी बिजली ज्यादा मिल रही है। गांवों में भी उपभोक्ता वस्तुएं पहुंची हैं। इससे बेशक पारंपरिक संस्कृति चोट भले ही पहुंची हो। यह भी सच है कि ग्रामीण विकास और दूसरी कल्याण योजनाओं के जरिए गांवों में केंद्रीय और राज्य सरकारों की ओर से पैसा जा रहा है। लेकिन यह भी सच है कि उस पैसे का एक बड़ा हिस्सा जमीनी स्तर पर खर्च होने की बजाय नौकरशाही और राजनीतिक रिश्ते के रूप में शहरी इलाकों में ही रुक रहा है और वहां निवेशित हो रहा है। इस लिहाज से देखें तो ग्रामीण इलाके में जैसी समृद्धि दिखनी चाहिए।

मंदी के चपेट में आने वाले

सताश सह

बजट समाह के पहल दिन याना 27 जनवरी का शेयर बाजार में निवेशकों को 9.5 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। विगत कुछ दिनों से निवेशकों को शेयर बाजार में लगातार नुकसान हो रहा है। हालांकि, इसका कारण देश में मदी की आहट कर्तव्य नहीं है। इसका मुख्य कारण अमेरिका के सेंट्रल बैंक द्वारा भारत में बजट पेश करने से पहले नीतिगत निर्णय की घोषणा करने की संभावना, चीन के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्टार्टअप डीपसीक मॉडल की लोकप्रियता में वृद्धि, भारतीय कंपनियों के दिसम्बर तिमाही के नतीजे का अपेक्षित नहीं रहना आदि हैं। दरअसल, भू-राजनैतिक संकट, लाल सागर में हूती विद्रोहियों की उपस्थिति आदि के कारण भारत के आयात-निर्यात तथा आपूर्ति श्रृंखला पर नकारत्मक प्रभाव पड़ रहा है और आर्थिक गतिविधियों में कमी आने के कारण कंपनियों का तिमाही मुनाफा कम हो रहा है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) ने 7 जनवरी 2025 को सकल घेरू उत्पाद (जीडीपी) का वित्त वर्ष 2024-25 के लिए पहला अग्रिम अनुमान जारी किया और इस अवधि में रियल जीडीपी वृद्धि दर के 6.4 प्रतिशत रहने का अनुमान जताया है, जो पिछले वित्त के दौरान 8.2 प्रतिशत रही थी। वहीं, भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान रियल जीडीपी के 6.6 प्रतिशत की दर से आगे बढ़ने का अनुमान जताया है। एनएसओके अनुसार नॉमिनल जीडीपी वित्त वर्ष

आसार हैं, लेकिन इसके कई दुष्परिणामों को दृष्टिगत करके मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) और केंद्रीय बैंक, रेपो दर में कटौती करने से गुरेज कर रही है। अगर हम वैश्विक अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर से भारतीय अर्थव्यवस्था की तुलना करें तो हमारी अर्थव्यवस्था वैश्विक स्तर से बहुत ऊपर है। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (ओईसीडी) के अनुसार 2024 में वैंक जीडीपी वृद्धि दर 3.2 प्रतिशत रही और 2025 में 3.3 प्रतिशत रह सकती है। वहीं, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) के मुताबिक वैंक अर्थव्यवस्था 2024 में 3.1 प्रतिशत और 2025 में 3.2 प्रतिशत की दर से आगे बढ़ सकती है। दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका से भी भारतीय अर्थव्यवस्था बेहतर स्थिति में है और आगामी वर्षों में भी इसके मजबूत बने रहने के आसार हैं। वित्त वर्ष 2024 के दौरान अमेरिका में विकास दर के 2.7 प्रतिशत और वित्त वर्ष 2025 में 2.0 प्रतिशत रहने का अनुमान है। वित्त वर्ष 2024-25 की पहली तिमाही में जीडीपी वृद्धि दर के 6.7 प्रतिशत रहने और दूसरी तिमाही में 5.4 प्रतिशत रहने के बाद कुछ अर्थशास्त्री और कुछ देसी एवं वैंक एजेंसियां भारतीय अर्थव्यवस्था के मंदी के गिरफ्त में आने की बात कर रहे हैं, लेकिन मंदी की परिभाषा के अनुसार जब किसी देश की वृद्धि दर सुस्त पड़ने लगती है, बेरोजगारी दर में इजाफा होता है और महंगाई दर ऊंची बनी रहती है तो वह देश मंदी की गिरफ्त में आ जाता है। यह भी माना जाता है कि किसी देश की जीडीपी में अगर दो तिमाहियों में लगातार गिरावट दर्ज की जाती है तो भी वह देश मंदी की चपेट में आ जाता है। इस परिस्थिती में मंदी के लक्षण भारतीय अर्थव्यवस्था में दृष्टिगोचर हो रहे हैं या नहीं इस बात की गहन पड़ताल करने की जरूरत है। जलदबाजी में यह कहना कि भारतीय अर्थव्यवस्था मंदी की गिरफ्त में आने वाली है, गलत होगा। कोरोना महामारी के दौरान अप्रैल 2020 में बेरोजगारी दर 23.50 प्रतिशत के स्तर पर पहुंच गई थी और सबसे कम सितम्बर 2022 में 6.40 प्रतिशत के स्तर पर रही थी। अभी मुद्रास्फीति की वजह से न कोई कंपनी बंद हुई है और न ही कामगारों की छंटनी की गई है। बेशक, चालू वित्त वर्ष में जीडीपी वृद्धि दर के घटकर 6.4 प्रतिशत रहने का अनुमान जताया गया है, लेकिन विगत 2 तिमाहियों में जीडीपी में गिरावट दर्ज नहीं हुई है। वित्त वर्ष 2024-25 की पहली तिमाही में यह 6.7 प्रतिशत और दूसरी तिमाही में 5.4 प्रतिशत रही है, लेकिन वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान जीडीपी वृद्धि दर 8.2 प्रतिशत रही थी। अभी आर्थिक गतिविधियों में सुरक्षी आने का एक बड़ा कारण मुद्रास्फीति है और शेरय बाजार में निवेशकों के पैसे ढूबने के दूसरे कारण हैं। रेपो दर में एक लंबे समय से कटौती नहीं की गई है, लेकिन रिजर्व बैंक के गवर्नर में बदलाव आने के बाद आगामी मौद्रिक समीक्षा में रेपो दर में कटौती करने के आसार है। तदुपरांत, उधारी के उठाव और आर्थिक गतिविधियों दोनों में तेजी आएगी। इससे इतर, अभी भी भारत की जीडीपी वृद्धि दर विश्व के प्रमुख देशों और औसत वैंक विकास दर से ज्यादा है।

सिद्धारमैया पर भ्रष्टाचार के आरोपों पर कांग्रेस चुप क्यों

यागद्र यागा

दरअसल कमज़ार हातों का ग्रेस में इतने क्षत्रप पनप गए हैं कि पार्टी चाह कर भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ऐसे में भ्रष्टाचार हो या पार्टी विरोधी गतिविधियां, कांग्रेस खिसकते जनाधार के कारण यह जहर पीने को मजबूर हो गई है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने दिल्ली में अपनी पहली चुनावी रैली को संबोधित करते हुए केजरीवाल पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अररिंवंद केजरीवाल पीएम मोदी की तरह झूठे बादे करते हैं। केजरीवाल ने कहा था कि भ्रष्टाचार मिटाएंगे लेकिन क्या दिल्ली में भ्रष्टाचार हटा क्या? अडानी पर भी केजरीवाल कुछ भी नहीं बोलते हैं। राहुल गांधी ने जब केजरीवाल पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए उसी समय कर्नाटक की कांग्रेस सरकार के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और अन्य के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय ने (ईडी) ने मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण (एमयूडीए) मामले के संबंध में 300 करोड़ रुपये के बाजार मूल्य वाली 142 अचल संपत्तियों को जब्त कर लिया। ईडी के बेंगलुरु जोनल कार्यालय ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत इन संपत्तियों को जब्त किया। ईडी के अनुसार, ये संपत्तियां विभिन्न व्यक्तियों के नाम पर पंजीकृत हैं जो पुलस मेसूर द्वारा भारतीय दड़ संहाता, 1860 और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की विभिन्न धाराओं के तहत सिद्धारमैया और अन्य के खिलाफ दर्ज की गई प्राथमिकी के आधार पर जांच शुरू की थी। आतंरिक तौर पर देखें तो राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खडगे में इतना साहस भी नहीं हो सका कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को मुख्यमंत्री पद से हटाना तो दूर बल्कि कारण बताओ नोटिस तक जारी कर सकें। दरअसल कांग्रेस को अंदाजा है कि यदि सिद्धारमैया से कुछ भी पूछा गया तो विद्रोह की नौबत आ जाएगी। ऐसे में कांग्रेस ने इस मुद्दे पर चुप्पी साधे रखना ही सही समझा। कांग्रेस को शायद यह बात समझ में नहीं आई कि उसकी चुप्पी ही उसे अपराधी बना रही है। यही वजह है कि भाजपा ने विगत चुनावों में भ्रष्टाचार के मुद्दों पर कांग्रेस की बिखिया उथड़ने में कोई कसर बाकी नहीं रखी। दरअसल कमज़ोर होती कांग्रेस में इतने क्षत्रप पनप गए हैं कि पार्टी चाह कर भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ऐसे में भ्रष्टाचार हो या पार्टी विरोधी गतिविधियां, कांग्रेस खिसकते जनाधार के कारण यह जहर पीने को मजबूर हो गई है। राजस्थान के पर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इसका उदाहरण है। सरेआउ उपेक्षा करने के बावजूद खिलाफकोई कार्रवाई तरह सचिन पायलट पार्टी विरोधी गतिरिक्ति किन्तु कांग्रेस उनकी रही है। गहलोत औंस तो सत्ता संघर्ष का ही न कांग्रेस राजस्थान भाजपा का मुकाबला करारी शिकस्त खाकरी कांग्रेस में भ्रष्टाचार वाले सिद्धारमैया अमें नीचे से लेकर खिलाफगंभीर मामल कि पार्टी चलाने वाले सोनिया गांधी और



उदाहरण हैं। सरेआर उपेक्षा करने के बावजूद खिलाफोर्ड कार्रवाच तरह सचिन पायलट पार्टी विरोधी गतिशील किन्तु कांग्रेस उनकी रही है। गहलोत औंसता संघर्ष का ही न कांग्रेस राजस्थान भाजपा का मुकाबला करारी शिकस्त उ कांग्रेस में भ्रष्टाचार वाले सिद्धारमैया अमें नीचे से लेकर खिलाफांगभीरा मामल कि पार्टी चलाने वाली सोनिया गांधी और

कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, उनके बेटे राहुल गांधी और अन्य कांग्रेस नेता फँसे हैं। बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी का आरोप है कि यह सब कुछ दिल्ली में बहादुर शाह जफर मार्ग पर स्थित हेरल्ड हाउस की 16 सौ करोड़ रुपये की बिल्डिंग पर कब्जा करने के लिए किया गया। वर्ष 2013 में अगस्ता वेस्टलैंड वीआईपी हेलीकॉप्टर खरीद घोटाला में सीबीआई और दूसरी केंद्रीय एजेंसियां अहमद पटेल पर इतालवी चॉपर कंपनी अगस्ता वेस्टलैंड से कमीशन लेने के आरोपों की जांच कर रही हैं। इस मामले में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ के भांजे रतुल पुरी भी फँसे हैं। राजस्थान में एंबुलेस घोटाला में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट भी आरोपी हैं। ये मामला 2010 से लेकर 2013 तक एनआरएचएम के तहत एंबुलेंस खरीदने में हुई धांधली का है। ईडी अब तक 12 करोड़ की संपत्तियां आरोपियों से जब्त कर चुकी है। कांग्रेस के दिग्गज नेता डीके शिवकुमार के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति दर्ज करने का मामला चल रहा है। 2017 में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने डीके शिवकुमार के 64 टिकानों पर जबरदस्त छापेमारी की थी। टैक्स चोरी की शिकायतों पर यह कार्रवाई हुई थी। हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता वीरभद्र सिंह के खिलाफ भी केंद्रीय एजेंसियों ने छापेमारी की।

